



## Mirza International Limited

Registered & Head Office :  
A-71, Sector-136, Noida,  
Uttar Pradesh, India- 201301  
Ph. +91 0120 7158766  
CIN : L191 29UP1979PLC004821  
Email : [marketing@mirzaindia.com](mailto:marketing@mirzaindia.com)  
Website : [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in)

May 26, 2025

<b>BSE Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001  <b>Scrip Code: 526642</b>	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051  <b>NSE symbol: MIRZAIN</b>
---	---

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Newspaper advertisement pertaining to Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025.**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025. The advertisements were published in English and Hindi newspapers today.

This information will also be hosted on the Company's website, at [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in)

This is for your information and records.

Yours faithfully,

For **Mirza International Limited**

**Harshita Nagar**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl.: As above.



# विश्व में युद्ध का बढ़ता कारोबार

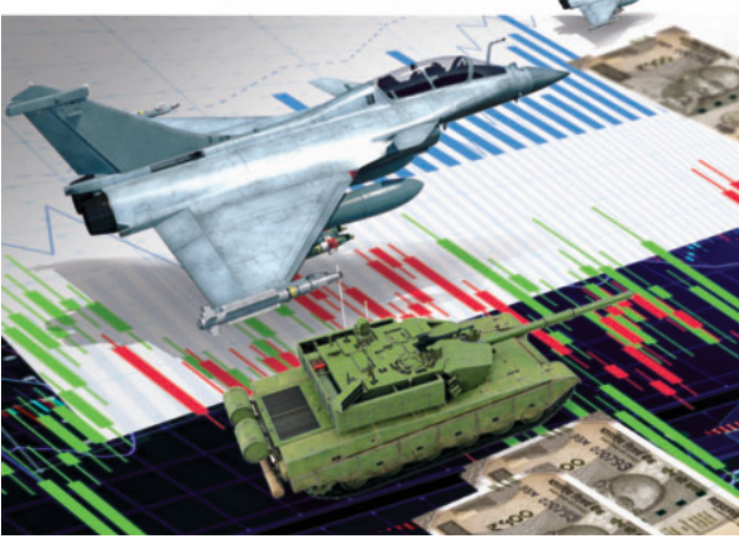
दुनिया भर में रक्षा हथियारों के बाजार में तेजी से विस्तार हो रहा है और भारत एक प्रमुख आयातक देश के रूप में उभरा है, हालांकि देश अब घरेलू रक्षा क्षेत्र के विकास पर जोर दे रहा है

शिखा शालिनी

दुनिया भर में युद्ध से जुड़े रक्षा हथियारों के आयात-निर्यात में वर्ष 2000-10 के दशक की तुलना में 2011 से 2024 के दशक के बीच अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। वैश्विक सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों पर शोध करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोखा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने सिपरी के आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसके मुताबिक, वैश्विक हथियार बाजार में अमेरिका का दबदबा अब भी बरकरार है और उसने हथियारों के बलवृत्ते वर्ष 2023 में 316.75 अरब डॉलर की कमाई की है। अमेरिका की हथियारों से हुई कमाई दूसरे स्थान पर रहे चीन को हथियारों से मिले कुल राजस्व के तीन गुना से भी अधिक है। इन आंकड़ों के एक दिलचस्प रुझान के मुताबिक प्रमुख सैन्य शक्ति होने के बावजूद, चीन के हथियार आयात में 47 प्रतिशत कमी आई है जो रक्षा क्षेत्र में उसकी बढ़ती घरेलू क्षमता और आत्मनिर्भरता के संकेत देती है।

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी. खंडारे ने वर्ष 2000 से ही वैश्विक हथियारों के आयात-निर्यात में वृद्धि का श्रेय चीन के रक्षा से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में आई तेजी को दिया है जिसके कारण उन देशों को एक विकल्प मिला है जो पहले अमेरिका पर निर्भर थे। उन्होंने कहा, 'इसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के हथियारों की बिक्री बढ़ी और यूरोप के रक्षा हथियार उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी कम हो गई। दरअसल चीन उन देशों में बिक्री पर जोर दे रहा है जहां हथियारों का आयात करने की होड़ है और यह अर्थव्यवस्था के रक्षा हथियारों की बिक्री के मॉडल से अलग है।'

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल बी.के. चतुर्वेदी अमेरिका और चीन के बीच हो रही इस प्रतिस्पर्धा को एक वैचारिक टकराव के रूप में देखते हैं जिसके मुताबिक अमेरिका एकध्रुवीय विश्व के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहता है जबकि चीन का जोर बहुध्रुवीयता पर है।



## सैन्य साजो सामान से जुड़ीं प्रमुख वैश्विक कंपनियां

रैंक	कंपनी	देश	कुल राजस्व	हथियारों से होने वाली कमाई	कुल राजस्व का फीसदी हिस्सा
1	लॉकहीड मार्टिन	अमेरिका	67,570	60,810	90
2	आरटीएक्स	अमेरिका	68,920	40,660	59
3	नॉर्थरॉप ग्रममैन	अमेरिका	39,290	35,570	91
43	एचएएल	भारत	3,910	3,710	95
71	बीईएल	भारत	2,400	1,940	81
98	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स	भारत	1,150	1,090	95

स्रोत: सिपरी आर्म्स इंस्ट्रुटी डेटाबेस, राजस्व मिलियन डॉलर में, आंकड़े 2023 के

### चीन का घरेलू निर्माण पर जोर

भारत दुनिया का प्रमुख हथियार आयातक देश है जिसके आयात में एक दशक के दौरान 104 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। एशिया क्षेत्र में होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है। लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे ने चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमता को अमेरिका के समुद्री रक्षा क्षेत्र के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती बताया है। वह कहते हैं, 'चीन के रक्षा क्षेत्र की संरचना में एक रणनीतिक

बदलाव देखा जा रहा है जिसमें सेना के कर्मियों को नौसेना में स्थानांतरित करना और नौसेना का अनुभव एवं परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए वैश्विक समुद्री डकैती विरोधी अभियानों का इस्तेमाल करना शामिल है।' भारत ने इस बीच अपने पारंपरिक साझेदार रूस के अलावा अन्य हथियार आपूर्तिकर्ता देशों से जुड़कर भागीदारी में विविधता लाने की कोशिश की है। भारत की प्रमुख रक्षा खरीद में रूस की एस-400 मिसाइल प्रणाली, फ्रांस

# राज्य, केंद्र मध्यम अवधि के लक्ष्यों पर कर रहे काम

ध्रुवाक्ष साहा

नीति आयोग ने राज्यों को लघु और मध्यम अवधि के लक्ष्य तैयार करने के लिए कहा है। नीति आयोग ने '2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य' योजना के अंतर्गत विकास लक्ष्य पूरे करने के लिए यह रणनीति अपनाने के लिए कहा है। इनमें 2047 तक भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर की प्रतिस्पर्धा करने के लक्ष्य के साथ ही 2030 और 2035 तक सटीक एवं पूरे किए जाने वाले लक्ष्य भी शामिल हैं।

2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत आधारभूत सुधारों, त्वरित सफलताओं, विशेष परियोजनाओं पर बदलाव के शुरुआती संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किए जाएंगे। जहां तक मध्यम अवधि के लक्ष्यों का सवाल है तो नीति आयोग के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार राज्यों को संस्थागत बदलाव, वृहद स्तर पर बुनियादी ढांचों के विकास, विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिस्पर्द्धी बनाना और समावेशी सामाजिक बदलाव पर जोर देना होगा।

नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक के बाद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'तत्कालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखने से केंद्र को यह जानने में मदद मिलती है कि किन मोर्चों पर राज्यों की मदद करनी है। यह रणनीति अपनाकर सामाजिक, भौतिक एवं डिजिटल ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक के निर्यात से जुड़े विषयों पर अधिक लाभकारी चर्चा करने में मदद मिलती है।' आयोग के अनुसार अगले दो दशकों में भारत का आकार उसकी मौजूदा स्थिति की तुलना में लगभग 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2047 में भारत का जो स्वरूप दिखेगा उसका 80 प्रतिशत हिस्सा अगले दो दशकों में तैयार होगा। आयोग के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से ही यह संभव हो पाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है, 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य पहली शर्त है।'

गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य अपने दृष्टिकोण पत्र पहले ही तैयार कर चुके हैं और मध्यम अवधि के लक्ष्य निर्धारित कर लिए



गए हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार शनिवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक के दौरान अवसंरचना और लॉजिस्टिक पर कई राज्यों ने प्रमुखता से जिक्र किया था। पिछले केंद्रीय बजट में घोषित पूर्वोदय योजना में आने वाले राज्यों में ज्यादातर इस ढांचे में शामिल किए जा चुके हैं या शामिल कर लिए जाएंगे। बैठक के बाद आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम और सदस्य रमेश चंद ने कहा कि एक समिति (चंद की अध्यक्षता में) ने पूर्वोदय योजना के लाभार्थी राज्यों

ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश के लिए योजना निर्धारित तैयार की है।

चंद ने कहा, 'राज्य अपनी प्रतिक्रियाएं एवं अपने सुझाव देंगे और हम 15 जून तक रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी।'

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक की निर्बाध निर्यात नीति परिषद के साथ मिलकर राज्य आर्थिक मंच की भी शुरुआत की। यह मंच राज्यों के पास उपलब्ध रकम का विश्लेषण करेगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा।

## जापान को पीछे छोड़ भारत चौथी सबसे

## बड़ी अर्थव्यवस्था बना: नीति आयोग सीईओ

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रह्मण्यम ने नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुल मिलाकर वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उन्होंने कहा, 'मैं जब बोल रहा हूं, तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज हम 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रह्मण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ा है। उन्होंने कहा, 'केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं और अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं, तो ढाई-तीन साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

होंगे।' भारत 2024 तक दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उन्होंने कहा, 'अगर हम अपनी योजना और सोच-समझ पर कायम रहे, तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे।' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल में

जारी अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य ('डब्ल्यूईओ') रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2025 में 4190 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

भाषा

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**  
(भारत सरकार का उपग्राम)  
प्र. का. संचालन विभाग  
ई-मेल: [ho.god@psb.co.in](mailto:ho.god@psb.co.in)  
जहाँ सेवा ही जीवन — जैव है

**पॉजिटिव पे प्रणाली के लिए आवश्यक सूचना**  
(दिनांक 01.06.2025 से सीटीएस में ₹10 लाख और उससे अधिक राशि के लिए पीपीएस अनिवार्य)  
भारतीय रिजर्व बैंक के अधीनस्थ संख्या डीपीएसएफ.सीओ.आरपीपीसी.सं. 309 / 04.07.005 / 2020-21 दिनांकित 25.09.2020 के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूझा बढ़ाने और वृहत मूल्य के शेकों के प्रमुख वितरणों की पुनः पुष्टि करके बैंक संबंधी घोषणाओं को न्यूनात्म करने के लिए 01 जनवरी, 2021 से बैंक ट्रेंडिंग प्रणाली (सीटीएस) में ₹50,000/- और उससे अधिक राशि वाले बैंक के लिए पॉजिटिव पे प्रणाली (पीपीएस) का अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।  
अब, बैंक ने 01 जून, 2025 से सीटीएस में ₹10 लाख और उससे अधिक राशि के बैंक के लिए पॉजिटिव पे प्रणाली (पीपीएस) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।  
नोट: ग्राहक द्वारा सीटीएस में बैंक प्रस्तुत करने के दौरान पीपीएस अधिदेश नहीं दिए जाने की स्थिति में बैंक का भुगतान नहीं करेते हुए 'सूचना प्राप्त नहीं हुआ' कारण लिखकर बैंक को वापस कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्रबंधक  
(संचालन विभाग)



# MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN : L39129UP1979PLC004821

Regd. Off. : A 71, Sector 136, Noida 201 301, Uttar Pradesh

website : [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in) ; e-mail : [compliance@mirzaindia.com](mailto:compliance@mirzaindia.com) ; Tel. : +91 120 7158766

**EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2025**

(Rs. in Lakh except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)		
1	Total Income from Operations	12073.04	11430.96	14306.35	57024.52	60939.67	12240.50	11491.79	15295.30	58274.86	63837.13		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(99.53)	(955.12)	111.61	(473.81)	1820.03	(413.79)	(783.40)	140.98	(355.11)	1659.61		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(99.53)	(955.12)	111.61	(473.81)	1820.03	(413.79)	(783.40)	140.98	(355.11)	1659.61		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(50.43)	(736.62)	68.11	(398.81)	1344.03	(439.66)	(568.64)	121.92	(354.38)	1206.83		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(228.22)	209.91	313.09	(543.41)	1364.55	(623.92)	462.75	354.95	(416.89)	1250.52		
6	Equity Share Capital	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet of the previous year	-	-	-	43613.37	44192.81	-	-	-	53672.72	52497.10		
8	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing & discontinued operations)												
1.	Basic:	(0.04)	(0.53)	0.05	(0.29)	0.97	(0.32)	(0.41)	0.09	(0.26)	0.87		
2.	Diluted:	(0.04)	(0.53)	0.05	(0.29)	0.97	(0.32)	(0.41)	0.09	(0.26)	0.87		

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on company's website at [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in)

b) The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company), Wholly Owned Subsidiaries (WOS) i.e. RTS Fashion Ltd and Genesis Brands Private Limited, are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2025. The auditors of the Company have carried out an audit and provided Audited Financial Results for the year ended 31st March 2025.

d) Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary to make them comparable.



For Mirza International Limited  
Sd/-  
Tauseef Ahmad Mirza  
Managing Director  
(DIN : 00049037)

# मॉनसून का जल्द आना अच्छी बारिश की गारंटी नहीं

संजीव मुखर्जी

इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने करीब 8 दिन पहले 24 मई को दस्तक दे दी। सामान्य तौर पर मॉनसून की शुरुआत 1 जून से होती है। मगर यह पूर्वोत्तर भारत में काफी पहले आ गया जो इसकी सामान्य शुरुआत से करीब 12 दिन पहले है। इससे पहले 2009 में मॉनसून ने 23 मई को ही दस्तक दे दी थी।

मगर केरल में मॉनसून के जल्दी आने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देश भर में उसका प्रदर्शन शानदार रहेगा अथवा बारिश का वितरण समान होगा। अतीत में कई ऐसे उदाहरण हैं जब दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने अपनी सामान्य शुरुआत से पहले केरल तट पर पहुंच गया लेकिन बाद में देश भर में उसका प्रदर्शन शानदार नहीं रहा। मॉनसून की जल्द शुरुआत के बजाय जून से शुरू होने वाले अगले चार महीनों के दौरान बारिश की स्थिति एवं वितरण यह निर्धारित करेगा कि कित वर्ष 2026 में कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास की दिशा क्या रहेगी। मगर इस बार यह कुछ अलग दिख सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने अपने अप्रैल के पूर्वानुमान में कहा था कि 2025 में न केवल बारिश 'सामान्य से अधिक' यानी लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 105 फीसदी होगी बल्कि उसका वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है। साल 2009 से अब तक मौसम विभाग की पूर्वानुमान क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है।

वैज्ञानिकों ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की प्रगति कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव वाली स्थिति, समुद्र के ऊपर बारिश वाले बादल और हवाओं की ताकत आदि शामिल हैं।

इससे पहले 2009 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से पहले दस्तक दी थी, मगर उसके बाद बारिश की रफ्तार कम हो गई। उस साल करीब 23 फीसदी कम वर्षा के साथ मॉनसून सीजन का समापन हुआ था। वह पिछले कई दशकों के दौरान दर्ज की गई सबसे कम औसत बारिश थी।

साल 2009 में मॉनसून सीजन के समाप्त होने पर मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, उस साल जून से सितंबर की अवधि में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून एलपीए का 77 फीसदी था। उस दौरान देश के लगभग 60 फीसदी जिलों में बहुत कम या अपर्याप्त बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने कहा कि 2009 में मॉनसून ने सामान्य से करीब एक सप्ताह पहले 23 मई को केरल तट पर दस्तक दी थी। इसके बावजूद 8 से 20 जून के दौरान बारिश थम सी गई थी।

उसके बाद यह 3 जुलाई तक पूरे देश को कवर करने के लिए मॉनसून फिर सक्रिय हुआ जबकि उसकी सामान्य तारीख 15 जुलाई है। अगरत 2009 में मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में केवल एक कम दबाव का क्षेत्र बना था जो सितंबर के अगले महीने में भी बरकरार रहा। मौसम विभाग ने उस समय कहा था, 'वर्षा के कुल वितरण से पता चलता है कि सीजन की शुरुआत में भारी कमी कमी के कारण देश में कुल बारिश पूरे सीजन के



## बारिश

वर्ष	अनुमान	बारिश
2009	मई-23	-23
2010	मई-31	5
2011	मई-29	4.9
2012	जून-05	-3.6
2013	जून-01	8.6
2014	जून-06	-10.1
2015	जून-05	-12.7
2016	जून-06	-0.3
2017	जून-30	-2.6
2018	जून-29	-7.4
2019	जून-08	11.8
2020	जून-01	10.5
2021	जून-03	0.4
2022	मई-29	6.5
2023	जून-08	-6
2024	मई-30	8
2025	मई-24	--

नोट - हर साल केरल में 1 जून को मॉनसून दस्तक देता है, स्रोत - मौसम विभाग

दौरान हर सप्ताह सामान्य से 19 फीसदी अथवा इससे अधिक कम रही।' मौसम विभाग ने स्वीकार किया कि 2009 में पूरे देश में और दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर चार अन्य क्षेत्रों में मौसमी वर्षा के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान सटीक नहीं था। मगर उसके 16 साल बाद यानी 2025 में विभाग ने कहा है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 'सामान्य से बेहतर' रहेगा जो एलपीए का 105 फीसदी होगा। विभाग का यह पूर्वानुमान 5 फीसदी घट-बढ़ की मॉडल त्रुटि के साथ है। उम्मीद है कि 2025 में 2009 को दोहराया नहीं जाएगा।

# भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट के टी1 का बाहरी हिस्सा हुआ प्रभावित

दीपक पटेल

रविवार तड़के भयंकर तूफान और भारी बारिश के कारण दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का कामकाज ठप हो गया। इस वजह से 49 उड़ानों की दिशा बदलनी पड़ी और करीब 650 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। साथ ही, टर्मिनल 1 के आगमन क्षेत्र का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें आगमन क्षेत्र में ऊपरी हिस्से में लगे फेंकिक का हिस्सा फटता हुआ और पानी अंदर आता हुआ दिख रहा था। यह घटना पिछले साल 28 जून, 2024 को उसी टर्मिनल पर एक स्टील और कंक्रीट की छत गिरने की घटना के लगभग एक साल बाद हुई है, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी और आठ अन्य घायल हो गए थे। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियुक्त एक पैनल की जांच में छत गिरने का कारण डिजाइन में खामी, खराब कारीगरी और पर्याप्त रखरखाव न किया जाना



बताया गया था। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ( डायल ) ने रविवार को बताया कि शहर में देर रात 2 बजे के आसपास 30 से 45 मिनट के थोड़े वक़्त में ही 80 मिलीमीटर (मिमी) से ज्यादा बारिश हुई और हवा की गति 70-80 किलोमीटर (किमी) प्रति घंटा थी। भारत के मौसम विभाग ( आईएमडी )

के सफ़दरजंग स्टेशन ने रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच 81.2 मिमी बारिश और 82 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं दर्ज कीं।

डायल ने कहा, 'अचानक अधिक मात्रा में बारिश होने के कारण आईजीआई हवाई अड्डे और उसके आसपास अस्थायी रूप से पानी जमा हो गया, जिससे हवाई अड्डे का कामकाज थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ। अत्यधिक पानी जमा होने से रोकने के लिए, चरम स्थितियों के लिए ही किए गए उपाय के तहत टी1 आगमन क्षेत्र में लगे बाहरी कपड़े वाले हिस्से में दबाव दिखा हालांकि उसके कारण ही पानी निकालने में मदद मिली।'



IBC not a shield for violators of consumer rights



CONSUMER PROTECTION  
JEHANGIR B GAI

Saranga Anilkumar Aggarwal, proprietor of East & West Builders, had sold flats to various purchasers but defaulted in handing over possession. Alleging a deficiency in service and breach of contractual obligations, the buyers filed complaints against him before the National Consumer Commission, which directed the builder to complete construction, obtain the requisite occupancy certificate, and hand over possession. As Aggarwal failed to comply with these directions, the flat purchasers filed execution applications and initiated penal proceedings for non-compliance with the orders.

Aggarwal opposed the penal proceedings, offering various excuses to justify his failure to comply with the orders. His principal contention was that the National Commission could not proceed against him as he had applied for insolvency under Section 95 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016, and that the interim moratorium, which was in force, barred proceedings under the Consumer Protection Act.

The National Commission considered several judgments and concluded that the moratorium under the IBC applies only to debts and does not extend to consumer claims. It therefore overruled Aggarwal's objections and continued with the proceedings, which ultimately resulted in the imposition of 27 penalties.

Aggarwal challenged the penalties before the Supreme Court through a civil appeal. The apex court noted that the crux of the dispute was an important question of law: whether a consumer

commission could hold a party guilty of disobeying its order and impose a penalty despite a moratorium having been granted by the National Company Law Tribunal (NCLT). The Supreme Court noted that Section 94 of the IBC states that a moratorium applies only to debts not classified as "excluded debts" under Section 79(15) of the Code. These include liabilities arising from fines imposed by courts or tribunals, damages for negligence or breach of obligation, maintenance liabilities, student loans, and other prescribed debts. The Court held that the damages awarded by the National Commission constituted "excluded debts" under the IBC, and hence, the moratorium would not be applicable.

The Supreme Court also observed that the proceedings before the National Commission were initiated by home-

buyers and were not monetary claims of debtors. The penalties imposed were intended to deter unfair trade practices and to safeguard the interests of vulnerable consumers affected by delays caused by the developer.

The Court observed that staying such penalties would set a dangerous precedent where developers could indefinitely delay justice by invoking insolvency proceedings. It further noted that the moratorium under the IBC does not apply to criminal proceedings and pointed out that Section 27 of the Consumer Protection Act provides for imprisonment. These proceedings are regulatory in nature, meant to enforce statutory obligations and protect public interest. Hence, the provision cannot be considered to be meant merely for debt recovery.

By its order dated March 4, 2025, in the case of *Saranga Anilkumar Aggarwal v Bhavesh Dhirajlal Sheth*, passed by Justice Vikram Nath for the Bench along with Justice Prasanna Varale, the Supreme Court concluded that the IBC is not designed to shield individuals who violate consumer rights and attempt to escape from criminal prosecution. The appeal was accordingly dismissed.

The writer is a consumer activist

US GOVERNMENT DEBT DOWNGRADE

Is it time to rethink the US market exposure in your portfolio?

Investing in this market is essential for geographical diversification, exposure to tech leaders

SANJAY KUMAR SINGH & KARTHIK JEROME

Moody's Investors Service downgraded the United States (US) government's credit rating from AAA to Aa1 on May 16, 2025. This has sparked concern among Indian retail investors who have diversified globally, with many questioning whether to maintain, reduce, or exit their US fund holdings.

Why the downgrade happened

The downgrade stems from the US's widening fiscal deficit and elevated debt-to-GDP ratio. "The high level of debt-to-GDP ratio could make it difficult for the US to service its debt," says Pratik Oswal, chief of passive business, Motilal Oswal Asset Management Company (AMC).

Moody's was the last of the three major rating agencies to lower the US's rating, following the S&P (2011) and Fitch (2023).

Fixed income market impacted

The fixed-income market reacted to the downgrade, with the 30-year Treasury yield rising above 5 per cent as investors demanded higher returns for perceived risk.

Longer-term risks include rising borrowing costs and inflation. "If the cost of borrowing for the government goes up, then typically the cost for companies also rises," says Vishal Dhawan, chief financial planner, Plan Ahead Wealth Advisors. Higher borrowing cost could affect earnings and also cause inflation to move up.

The reaction in the equity markets has been muted. "The US market has large corporates, which are well entrenched and derive their revenue not just from the US market but globally," says Kaustubh Belapurkar, director-manager research, Morningstar Investment Research India.

Limited impact likely on dollar

Central banks have for some time been



hedging their risks by diversifying their reserves into other currencies and gold. "The debate around de-dollarisation will get more attention due to this downgrade," says Dhawan.

Experts do not expect the downgrade to have a material impact on the dollar's strength. "Most of the forex reserves across the world are still held in the dollar," says Oswal.

It may slightly weaken the dollar, which would reduce rupee-adjusted returns for Indian investors. "A one-notch downgrade from AAA may have some impact, but it will not be substantial," says Belapurkar.

Innovation hub

Indian investors should have some exposure to the US because it remains the world's foremost innovation hub. "If you want exposure to some of the leading AI companies, then the US market must be a part of your portfolio," says Oswal. Indian investors can get exposure to advanced semiconductors, pure-play electric vehicles, aerospace and defence, genomics, and other high-tech industries, which may not be available on Indian stock exchanges.

A bilateral trade agreement with the United Kingdom, a 90-day pause vis-à-vis China, and advanced negotiations with India have eased tensions. "The US appears to be softening its

stance on tariffs," says Dhawan.

Policy and earnings risks

Policy decisions and ongoing wars in several global hotspots pose risks. "Trade wars and geopolitical tensions could have a short-term impact on these funds," says Oswal.

Belapurkar points out that the imposition of reciprocal tariffs could stoke inflation. Dhawan adds that a global slowdown resulting from tariffs could affect US multinationals. If the US dollar weakens against the rupee, that would, to some extent, erode the returns of these funds.

Higher bond yields may also cause diversion of capital from equities, affecting returns from the latter asset class.

Above-average valuations

The S&P 500 currently trades above historical valuation averages. "The top 7-10 mega-cap companies especially have higher valuations as they are pricing in the opportunity in AI," says Oswal.

Sustaining these valuations will depend on earnings. "Only with double-digit growth can US equities sustain the kind of valuations they have currently," adds Dhawan.

Entry strategy for new investors

Investors with a long horizon may con-

sider US funds for diversification. "The US market has a low correlation with the Indian market," says Oswal.

He cites innovation leadership and long-term rupee depreciation as other reasons. The dollar has appreciated 3-4.5 per cent annually against the rupee over the past 15-20 years.

Belapurkar highlights Indian investors' home bias, and the domestic focus of many corporates as key reasons for global diversification. He advises that, rather than worry about valuations and wait for a correction, investors should begin investing systematically. Dhawan recommends global funds for investors who desire broader diversification.

Existing investors should maintain exposure

Oswal recommends 10-20 per cent equity exposure outside India. Investors should check their current US allocation against their targets and also factor in their dollar-linked goals, such as education and travel. "Investors with up to 20 per cent exposure should do nothing," says Dhawan. Those whose exposure has gone beyond this level should consider rebalancing.

Given rich valuations, investors should take the systematic investment plan route in US equities and enter with a seven-year-plus holding period.

**IFGL**

Registered Office:  
Sector 'B', Kalunga Industrial Estate  
P.O. Kalunga 770031, Dist: Sundergarh, Odisha  
Tel: +91 661 2660195  
E-mail: ifgl.works@ifgl.in

**IFGL REFRACTORIES LIMITED**  
CIN: L51909RJ2007PLC027954

**Head & Corporate Office :**  
McLeod House, 3, Netaji Subhas Road  
Kolkata 700001, Tel: +91 33 40106100  
E-mail: ifgl.ho@ifgl.in;  
investorcomplaints@ifgl.in

Website: www.ifglgroup.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025					
Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	45,221	38,173	40,116	167,044	165,826
Net Profit / (Loss) before Tax from Ordinary Activities	1,279	(196)	2,120	5,954	9,783
Net Profit after Tax and Exceptional Item	843	(218)	1,254	4,298	8,167
Total Comprehensive Income [Comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	1,586	(1,259)	966	6,019	9,223
Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per Share)	3,604	3,604	3,604	3,604	3,604
Other Equity	-	-	-	107,096	103,602
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)					
Basic and Diluted #	2.34	(0.60)	3.48	11.93	22.66

# Figures for quarters are not annualised.

**NOTES :**

- Above audited consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 24, 2025 and approved by the Board of Directors (Board) at their meeting held on that date. The Statutory Auditor have audited the same and issued an unmodified opinion.
- The Board of Directors of the Holding Company in their meeting held on May 7, 2025, had declared Interim Dividend at the rate of 60 % i.e. ₹ 6 per Equity Share of ₹ 10/- each face value.
- The Board of Directors of the Holding Company, at its meeting held on May 24, 2025, have proposed a final dividend of ₹ 1 (10%) per equity share for the financial year ended March 31, 2025 subject to the approval of shareholders of the Holding Company at the forthcoming Annual General Meeting and following policy on Dividend Distribution of the Holding Company. Proposed dividend is accounted for in the year in which it is approved by the shareholders.
- The Board of Directors of the Holding Company in their meeting held on May 24, 2025, have recommended issue of 1 (one) Equity Share of ₹ 10 each fully paid up of the Company as bonus share for every 1 (one) Equity Shares held, following statutory provisions applicable including Section 63 and other relevant Sections of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, SEBI LODR Regulations, SEBI ICDR Regulations and subject to approval of the shareholders of the Holding Company.
- In an earlier year, the Holding Company's claim for Assessment Year 2020-21 for ₹ 2,816 lakhs (tax impact of ₹ 984 lakhs) towards deduction on account of depreciation on goodwill arising on amalgamation was disallowed under Income Tax assessment proceedings and being aggrieved thereby, the Holding Company had filed an appeal. Income tax authorities have subsequently issued notices under section 148 of the Act for Assessment Years 2018-19 and 2019-20 thereby reopening assessments for said Assessment Years on the ground that similar claims of ₹ 5,006 lakhs (tax impact of ₹ 1,732 lakhs) and ₹ 3,755 lakhs (tax impact of ₹ 1,312 lakhs) in the Assessment Years 2018-19 and 2019-20 respectively escaped assessment as income. Being aggrieved, the Holding Company filed a writ petition before Hon'ble High Court on May 21, 2024. The Holding Company supported by legal opinion, continues to believe that aforesaid deductions claimed are sustainable on merit and remain unaffected.
- Key Stand-alone financial information are as follows :

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	27,299	23,518	21,590	101,386	90,959
Net Profit before Tax from Ordinary Activities	2,203	591	2,198	7,455	7,423
Net Profit after Tax from Ordinary Activities	1,691	502	1,556	5,760	6,511
Total Comprehensive Income [Comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	1,665	497	1,531	5,718	6,490

7. The figures of the last quarter ended March 31, 2025 and March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the financial year ended March 31, 2025 and March 31, 2024 and the unaudited published year to date figures up to December 31, 2024 and December 31, 2023, being the date of the end of the third quarter of that financial year which were subjected to Limited Review.

8. This is an extract of the detailed format of audited Consolidated and Stand-alone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Detailed format of the audited Consolidated and Stand-alone Financial Results are available on the Websites of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's Website (https://ifglgroup.com/investor/financial-performance/)



On behalf of the Board  
of IFGL Refractories Limited  
S K Bajoria  
Chairman  
(DIN : 00084004)

Kolkata  
May 24, 2025

**OUR TECHNOLOGY. YOUR SUCCESS.**

**MIRZA INTERNATIONAL LIMITED**  
CIN : L9129UP1979PLC004821

Regd. Off. : A 71, Sector 136, Noida 201 301, Uttar Pradesh  
website : www.mirza.co.in ; e-mail : compliance@mirzaindia.com ; Tel. : +91 120 7158766

**EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2025**

(Rs. in Lakh except EPS)											
Sl. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
		Refer Note 7	Refer Note 7	Refer Note 7							
1	Total Income from Operations	12073.04 (99.53)	11430.96 (955.12)	14306.35 111.61	57024.52 (473.81)	60939.67 1820.03	12240.50 (413.79)	11491.79 (783.40)	15295.30 140.98	58274.86 (355.11)	63837.13 1659.61
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)										
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(99.53)	(955.12)	111.61	(473.81)	1820.03	(413.79)	(783.40)	140.98	(355.11)	1659.61
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(50.43)	(736.62)	68.11	(398.81)	1344.03	(439.66)	(568.64)	121.92	(354.38)	1206.83
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(228.22)	209.91	313.09	(543.41)	1364.55	(623.92)	462.75	354.95	(416.89)	1250.52
6	Equity Share Capital	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04	2,764.04
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet of the previous year	-	-	-	43613.37	44192.81	-	-	-	53672.72	52497.10
8	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing & discontinued operations)										
1. Basic:		(0.04)	(0.53)	0.05	(0.29)	0.97	(0.32)	(0.41)	0.09	(0.26)	0.87
2. Diluted:		(0.04)	(0.53)	0.05	(0.29)	0.97	(0.32)	(0.41)	0.09	(0.26)	0.87

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.mirza.co.in
- The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company), Wholly Owned Subsidiaries (WOS) i.e.: RTS Fashion Ltd and Genesis Brands Private Limited, are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2025. The auditors of the Company have carried out an audit and provided Audited Financial Results for the year ended 31st March 2025.
- Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary to make them comparable.

Date : 24.05.2025  
Place: NOIDA

For Mirza International Limited  
Sd/-  
Tauseef Ahmad Mirza  
Managing Director  
(DIN : 00049037)

**MAWANA SUGARS LIMITED**  
CIN: L74100DL1961PLC003413

Registered Office : 5<sup>th</sup> Floor, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, New Delhi-110 125

Tel.: 91-11-25739103, Fax: 91-11-25743659, Email : corporate@mawanasugars.com, Website : www.mawanasugars.com

Statement of Standalone and Consolidated Audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2025													
(Rs. in crore except earning per share)													
S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated							
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited
		March 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2024	December 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2024
1	Total Income from operations	346.44	337.43	323.25	1,455.02	1,384.39	347.96	337.39	322.68	1,455.63	1,382.71		
2	Profit for the period/year (before tax and exceptional items)	78.60	21.92	63.97	69.95	57.98	78.46	21.96	62.66	68.08	53.04		
3	Profit for the period/year before tax (after exceptional items)	78.60	43.31	63.97	91.34	57.98	78.46	83.24	62.66	129.36	53.04		
4	Profit for the period/year after tax (after exceptional items)	61.81	32.58	48.39	71.40	42.59	61.67	72.51	47.08	109.42	37.65		
5	Total Comprehensive Income for the period/year {Comprising profit for the period/year and Other Comprehensive Income/(loss) for the period/year (after tax)}	61.46	32.58	48.40	71.05	42.60	61.32	72.51	47.09	109.07	37.66		
6	Equity Share Capital	39.12	39.12	39.12	39.12	39.12	39.12	39.12	39.12	39.12	39.12		
7	Other Equity as per balance sheet				452.94	409.27				452.81	371.12		
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)												
a) Basic and diluted		15.80	8.33	12.37	18.25	10.89	15.77	18.54	12.04	27.97	9.63		

Notes :

- The statutory auditors have carried out an audit of the standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2025. These audited financial results have been recommended by the Audit Committee at its meeting held on May 24, 2025 and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 24, 2025.
- The above is the extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2025, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 are available on the stock exchange websites. (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on the Company's website.
- The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("IndAS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.

Place: Gurugram  
Date : May 24, 2025

For Mawana Sugars Limited  
Sd/-  
Rakesh Kumar Gangwar  
(Managing Director)  
DIN No. 09485856

